

# भारत का याजपत्र

## The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राचिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई विल्सो, बुधवार, मार्च 8, 1972/फाल्गुन 18, 1893

No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 1972/PHALGUNA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न दो जाती हैं जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

### MINISTRY OF FOREIGN TRADE

#### PUBLIC NOTICES

#### IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th March 1972

SUBJECT:—Imports of Capital goods (Balancing Equipment) against the U.K. Kipping Loan VIII.

No. 40-ITC(PN)/72.—The U.K. Government have made available as part of the assistance for Indian Economic development, a loan of £ 1.0 million (Rs. 1.80 crores) to meet the requirements of U.K. oriented firms for balancing equipment.

2. It has been decided that these funds may be used for issue of licences to Actual Users in both the scheduled and non-scheduled sectors including small scale industries with equipment of British origin, for import of minor balancing equipment needed by them to maximise utilisation of equipment already in use. The amount available for the purpose being small as against the demand from entrepreneurs, it has been decided to consider applications only in those cases where:—

- (i) The equipment in use is mainly of British origin; and
- (ii) The value of the equipment sought to be imported is small in relation to the equipment already in use and does not exceed £ 25,000/- c.i.f. value.

Applications from eligible importers should be supported by information as per proforma given in the Appendix I to this Public Notice. In case, the application is not supported by the Appendix or incomplete/faulty information is given in the Appendix, the application will be summarily rejected. It may be particularly noted that only one application should be submitted by each eligible importer. More than one application submitted by an importer will not be considered.

3 The terms and conditions which will be applicable to the licences to be issued against this loan are given in the Public Notice No 180-ITC(PN)/71 dated 22nd December, 1971

4 Applications from eligible actual users for the imports of minor balancing equipments in terms of this Public Notice may be submitted in the prescribed form and manner (Form-E) to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi (Special Cell) by the 29th April, 1972

#### APPENDIX

1 Name and complete address of the applicant

- (a) Factory,
- (b) Registered Office

2 Nature of the concern, whether proprietary/partnership/Private Limited/Public Limited

3 Name of the Proprietors/Partners/Directors

4 Whether borne on the list of DGTD/DC(SSI)/Iron & Steel Controller etc. (Quote Registration No and date).

5 Whether the applicant is a small scale unit and if so, whether it will continue to remain so after the proposed import —

- (a) Present total assets
- (b) Total assets after import of equipment applied for
- (c) Present value of Plant & Machinery
- (d) Value of Plant & Machinery after the import of equipment asked for

6 Industry to which the application relates

7 Description of equipment applied for. If possible this may be furnished in the form of an annexure indicating the items to be imported and their respective cif value

8 (a) Details of import licences granted to the applicant during the last 12 months i.e. value of equipment source of financing whether imports effected etc

(b) Details of other applications separately made for import of Capital goods, which are still pending

9 Value of the present application.

10 Value of British Collaboration Technical or Financial. In case of financial collaboration, percentage of British Capital participation may be given

11 (a) Value of British Machinery currently in use

- (b) Value of indigenous machinery installed in the factory
- (c) Value of total machinery installed in the factory

12 Whether applicant holds an Industries (D&R) Act Licence

- (a) The items of manufacture for which the applicant holds Industrial Licences
- (b) The licensed capacity and the installed capacity
- (c) Actual production in 1970
- (d) Likely increase in the capacity after the import of the equipment asked for.

बिंदेश यादर में संघ

सार्वजनिक सूचना।

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1972

विषय यू० के० किंग लोन 8 के लिए पृजीगत माल (शेष उपस्कर) का आयात।

**संख्या 40 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 72**—मू० के० सरकार ने शेष उपस्कर के लिए अभिविन्यस्त व्यवसाय संघों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता के रूप में 10 लाख पौंड (1.80 करोड़ रुपये) का ऋण उपलब्ध होगा।

2. यह निश्चय किया गया है कि अनुसूची और गंर-अनुसूची वाले वोनों ही प्रकार के वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए जिसमें ब्रिटिश मूल के उपस्कर के साथ लघु पैमाने उद्योग भी शामिल हैं पहले से ही उपयोग में लगाए गए उपस्कर के उपयोग की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जरूरत ममत्वे जाने पर छोटे शेष उपस्कर के आयात के लिए लाइसेस जारी करने के लिए इन राशियों का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि उद्यमकर्ताओं की तरफ से माग अधिक है और धन-राशि इस कार्य के लिए कम इसलिए केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार करने का निश्चय किया गया है जो

- (1) जिस उपस्कर का व्यवहार किया जाता है वह ब्रिटिश मल का है, और
- (2) जिस उपस्कर का व्यवहार किया जा रहा है उसका मूल्य गहने से ही व्यवहार में आने वाले उपस्कर से कम है और सी०आई०एफ० मूल्य 25000 पौंड से अधिक नहीं है।

उपयुक्त आयतको द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र इस सार्वजनिक सूचना के परिणाम-1 में दिए गए प्रपत्र के अनमार सूचना में समर्थित होने चाहिए। यदि आवेदन-पत्र परिणाम द्वारा समर्थित नहीं है या अधूरा है परिणाम में गलत सूचना दी गई है तो ऐसी स्थिति में आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसे विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि प्रत्येक उपयक्त आयातक द्वारा केवल एक ही आवेदन-पत्र भेजा जाना चाहिए। आयातक द्वारा एक में अधिक जमा किए गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. इस नाइमेस के साथ लागू होने वाली शर्तें जो इस ऋण के लिए जारी की जाने वाली हैं, वे सार्वजनिक संचार सूचना 180-आ० टी० सी० (पी० एस) / 72 दिनांक 22 दिसम्बर 1971 में दी गई हैं।

4. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार छोटे शेष उपस्कर के आयात के लिए उपयुक्त वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र निर्धारित रूप में और वित्रि के साथ (फार्म-ई) मुझ्य नियन्त्रक आयात-नियात नई दिल्ली (विशेष मेल) को 29 अक्टूबर 1972 तक भेजा जा सकता है।

परिशिष्ट 1

1. आवेदक का नाम और पूरा पता :  
 (क) फैक्ट्री ।  
 (ख) पंजीगत कार्यालय
2. उद्योग किस प्रकार का है : स्वाम्य/भागीदारी/निजी परिसीमित/सार्वजनिक परिसीमित है ।
3. स्वामियों/भागीदारों/संचालकों का नाम ।
4. क्या डी० जी० टी० डी० डी०/डी० सी० (एस० एम० आई०)/लोहा और उस्पात नियन्त्रक आदि की सूची में है :  
 (पंजीयन संब्धा और तारीख दीजिए)
5. क्या आवेदक लघुपैमाने का है और यदि हाँ तो क्या प्रस्तावित आयात करने के बाद ऐसा ही उसे बनाए रखे :  
 (क) वर्तमान कुल परिसम्पत्ति ।  
 (ख) लागू होने वाले उपस्कर के आयात करने के बाद कुल परिसम्पत्ति ।  
 (ग) संयंत्र और मशीनों का वर्तमान मूल्य ।  
 (घ) मांग किए गए उपस्कर के आयात के बाद संयंत्र और मशीनरी का मूल्य ।
6. जिस उद्योग से आवेदन-पत्र सम्बन्ध रखता है ।
7. जिस उपस्कर के लिए आवेदन किया गया है उसका विवरण यदि सम्भव हो तो आयात की जाने वाली मदों और तत्सम्बन्धी सी० आई० एफ० मूल्य को प्रदर्शित करने वाले अनुबन्ध के रूप में भेजा जाय
8. (क) गत 12 महीनों के दौरान आवेदक को प्रदान किए गए आयात लाइसेंसों का विवरण अर्थात् उपस्कर का मूल्य अर्थयुक्त बनाने के साधन जहाँ तक आयात को प्रभावित किया आविद ।  
 (ख) उन अन्य आवेदन-पत्रों का विवरण जो पंजीगत माल के लिए अलग से दिए गये थे और जो भी अभी विचाराधीन है ।
9. वर्तमान आवेदन-पत्र का मूल्य ।
10. तकनीकी या अर्थयुक्त वाले श्रिटिश सहयोग का मूल्य आविद अर्थयुक्त प्रयोग वाला है तो श्रिटिश पूंजी सहयोग का प्रतिशत दिया जाए ।
11. (क) वर्तमान प्रयोग में आने वाली श्रिटिश मशीनों का मूल्य  
 (ख) फैक्ट्री में लगाई गई देशी मशीनों का मूल्य ।  
 (ग) फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों का कुल मूल्य ।

12. क्या आवेदक के पास उद्योग (डी० एण्ड आर) अधिनियम लाइसेंस है ?

- (क) आवेदक के पास जो ओद्योगिक लाइसेंस है उसके लिए निर्माण की जाने वाली मर्दे
- (ख) लाइसेंस द्वारा प्रदान की क्षमता और लगाई गई मशीन की क्षमता
- (ग) 1970 का वास्तविक उत्पादन ।
- (घ) मांग किए गए उपस्तर के आधार के बाद क्षमता में वृद्धि की सम्भावना ।

**SUBJECT:**—Issue of import licences to Established Importers against the U.K. Kipping Loan VIII.

**No. 41-ITC(PN)/72.** The U.K. Government have made available as part of the assistance for Indian economic development a loan of £ 1 million (Rs. 1.80 crores) to meet the requirements of U.K. oriented firms, for import of spare parts required for servicing U.K. equipment in the country.

2. It has been decided that this loan may be used for issuing licences for import of spares to the representatives of British manufacturers of machinery and equipment, who have been receiving import licences as established importers or under earlier Kipping Loans, to import spare parts needed for servicing and maintaining the equipment supplied by their principals. Licences will also be issued to Established Importers for import of spares for printing machinery and mining machinery manufactured in the U.K.

3. As the amount available for the purpose is relatively small, preference will be given to importers of spare parts who have commitments to service existing equipment of British origin. Applications from eligible importers should be supported by information as per proforma given in the Appendix I to this Public Notice. In case, the application is not supported by the Appendix or incomplete/faulty information is given in the Appendix, the application will be summarily rejected. It may be particularly noted that only one application should be submitted by each eligible importer. If more than one application is submitted by an importer only the first application will be considered.

4. The terms and conditions which will be applicable to the licences to be issued against this loan are given in the Public Notice No. 180-ITC(PN)/71 dated 22nd December, 1971.

5. Applications may be submitted in the prescribed form and manner to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi (Special Cell) by the 29th April, 1972.

#### APPENDIX

#### Proforma

1. Name of the firm.
2. Whether the importer has any British Collaboration—Technical or Financial.
3. (a) In case the importer has financial collaboration the percentage of British Capital participation may be given.
3. Details of quota certificates held by the importer may be given as follows:—

Certificate No.	Date	Quota items	Value /lakhs	Rs.
-----------------	------	-------------	-----------------	-----

(i)

(ii)

(iii)

(a) Total value (in Rs.) of all the quota certificates held by the importers.

4. Value of actual imports as established importer from the U.K. during 1968-69, 1969-70 and 1970-71 may be given as follows:—

Category of Imports	1968-69	1969-70	1970-71
(Value in Indian Rupees)			
(a) Imports against Quota licence . . . .			
(b) Imports against earlier Kipping Licences in the capacity of Established Importer			
(c) All-hoc licences issued to manufacturers for import of stock and sale spare parts . . . .			
<b>TOTAL</b>			

NOTE.—Separate figures must be given for each category of imports. The import figures should be certified by the Auditors.

5. Name of the British Manufacturer(s) whom, where possible, the Indian Importer is representing and the approximate value of each equipment in use in India.

Signature:—

for and on behalf of:—

M. M. SEN,  
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : यू० के० किप्पिंग लोन 8 के लिए संस्थापित आयातकों को आयात लाइसेंस जारी किया जाना।

संख्या 41—आई० टी० सी० (पी० एन०) / 7.—यू० के० सरकार ने हमारे देश में यू० के० उपस्कर को काम में लाने के लिए अपेक्षित फालतू पुजों के आयात के लिए प्रभिविन्यस्त व्यवसाय संघों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता के रूप में 10 लाख पौँड (1.80 करोड़ रुपये) का ऋण उपलब्ध कराया है।

2. यह निश्चय किया गया है कि इस ऋण का उपयोग मशीन तथा उपस्कर के ब्रिटिश निर्माण कर्ता के उन प्रतिनिधियों के लिए किया जाएगा जो संस्थापित आयातकों के रूप में या पूर्व किप्पिंग लोन के अन्तर्गत उनकी पूजी द्वारा दिए गए उपस्कर को काम में लाने और उन्हें चालू रखने के लिए आवश्यकता होने पर फालतू पुजों के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करते आ रहे हैं। मुद्रण मशीनें तथा खनन मशीनें, जो यू० के० में बनाई गई हैं, उनके लिए काम आने वाले फालतू पुजों के आयात लाइसेंस भी संस्थापित आयातकों को दिए जाएंगे।

3. चूंकि इस कार्य के लिए उपलब्ध धन राशि अपेक्षाकृत कम है, इसलिए उन आय तकों को वरीयता दी जाएगी जो ब्रिटिश मूल के वर्तमान उपस्कर को मुचारू रूप में चलाने के फालतू पुजों के आयात के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। उपयुक्त आयातकों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सूचना से समर्थित होने चाहिए। यदि आवेदन-पत्र परिशिष्ट द्वारा समर्थित नहीं हैं या अधूरा हैं / परिशिष्ट में गलत सूचना दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन-पत्र को सरकारी तौर पर अम्बीकृत कर दिया जाएगा। इसे विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि प्रत्येक उपयुक्त आयातक द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए। आयातक द्वारा एक से अधिक भेजे गये आवेदन पत्रों की स्थिति में केवल पहले पर ही विचार किया जाएगा।

4. इस क्रण के विपरीत लाइसेंसों के लिए जो लागू नियम तथा शर्तें जारी की जाएंगी वे सार्वजनिक सूचना सं० 180 आई ई० सी० (पौं एन०) 71, दिनांक 22-12-1971 में दी गई है ।

5. निर्धारित रूप में और विधि के साथ आवेदन-पत्र, मूल्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित नहीं दिल्ली (विशेष सेल) को 29 अप्रैल, 1972 तक दिये जा सकते हैं।

### परिशिष्ट 1

#### प्रपत्र

1. उद्घोग संघ का नाम ।

2. क्या आयातक के पास कोई ब्रिटिश सहयोग तकातीकी या अर्थयुक्त वाला है ?

3. (क) यदि आय, रक अर्थयुक्त सहयोग वाला है, तो ब्रिटिश पूँजी सहयोग का प्रतिशत दिया जाय

3. आयातक द्वारा रखे गए कोटा प्रमाण-पत्रों के विवरण निम्नलिखित के रूप में विए जा सकते हैं :—

प्रमाण-पत्र की संख्या	दिनांक	कोटा की मद्दें	मूल्य लाख रुपयों में
( 1 )			
( 2 )			
( 3 )			

(क) आय तकों द्वारा रखे गए सभी कोटा प्रमाण-पत्रों का कुल मूल्य (रुपये में)

4. 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान यू० के० से आयात करने वाले के रूप में संस्थापित आस्तविक आयातों का मूल्य निम्नलिखित के अनुसार दिया जा सकता है :—

आयातों की श्रेणी	1968-69	1969-70	1970-71

(भारतीय रुपये में मूल्य)

( 1 ) कोटा लाइसेंस के विपरीत आयात ।

( 2 ) संस्थापित आयातों के रूप में पूर्व किभिंग लाइसेंसों के विपरीत आयात ।

(3) संचयन और बिक्री फालसू  
पुजों के आयात के लिए निर्माण-  
कर्ताओं को जरी किए गए तर्दश्य  
लाइसेंस

कुल

टिप्पणी.—आयातकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग आंकड़े अवधारणा दिए जाने चाहिए।  
आयात आंकड़े लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

5. जहां सम्भव हो, उन ब्रिटिश निर्माण-षट्ठी का नाम दें, जिसका भारतीय आयातक प्रति-  
निधित्व कर रहा है और भारत में प्रयोग कि जाने वाले प्रत्येक उपरकर का अनुमानिक  
मूल्य दें।

हस्ताक्षर.....

वास्ते और के बदल.....

एम० एम० सेन,  
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।